

**Press Information Bureau
Government of India
Prime Minister's Office**

08-February-2016 10:48 IST

Text of PMs address while dedicating the Paradip Refinery to the Nation

जय जगन्नाथ! विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों।

सरकारी कार्यक्रम तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा माहौल कभी देखा नहीं है। मेरी जहां भी नज़र जा रही है, लोग ही लोग है। यह इस बात का सबूत है कि ओडिशा का हर नागरिक जनता है कि इस पारादीप रिफाइनरी का उनके जीवन में कितना महत्व है, ओडिशा के विकास के लिए कितना महत्व है। वो हर ओडिशा का नागरिक जानता है। मैं आप सब को हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में, विकास के इस काम में भागीदार बनने के लिए हमारे बीच आए हैं।

ओडिशा, ये उत्कल मणि, पंडित गोकोवंद दास जी, उत्कल गौरव मधुसूदन दास जी, बीर सुरेन्द्र साय जी एवं महाराष्ट्र के कृष्ण चंद्र गजपति जैसे महान महापुरुषों को, आत्माओं को मैं नमन करता हूं।

सैंकड़ों सालों तक ओडिया व्यवसायी, साधव समुद्री रास्ते से दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों के विभिन्न स्थानों जैसे – जावा, बाली, सुमात्रा, बॉरनियो कहां-कहां पहुंचते थे ओडिशा के व्यापारी। इसकी याद में हर साल आज भी पवित्र कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रदेश के कोने-कोने में बोइत वंदना की जाती है। पारंपरिक रूप से यहां के बंदरगाह विश्व के अन्य भागों से व्यापार के लिए बहुत ही vibrant हुआ करते थे। महाकवि कालिदास ने रघुवंशम काव्य में कलिंग के राजा को महोदधिपति यानी lord of the sea, इस रूप में वर्णन किया है। मैं इस पारादीप जगतसिंहपुर जिले की माटी को भी पावन क्षेत्र मानता हूं। यही धरती है जहां शुद्र मुनि सारलादास ने संपूर्ण महाभारत की रचना की और यह संस्कृत के अलावा किसी भी भारतीय भाषा में सबसे पहले लिखी गई महाभारत थी।

अत्यधिक विनम्रता के साथ मैं आज उत्कल केसरी हरि कृष्ण मेहता और उत्कल के महान पुत्र श्री बीजू बाबू को याद करना चाहता हूं। यही तो महापुरुष थे जिन्होंने पारादीप को बचाने के लिए बंदरगाह की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। इस जगतसिंहपुर जिले की मिट्टी में ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान नबकृष्ण चौधरी, स्वतंत्रता सेनानी गोपोबंधु जी, मालती देवी जी और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्राण कृष्ण परिजा, ये ऐसे महापुरुष हैं, जिनको याद करके मैं सर झुकाता हूं, उनको नमन करता हूं।

भाइयों-बहनों, यह मेरे लिए विशेष सौभाग्य का विषय है कि 35,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई हिन्दुस्तान की रिफाइनरियों में सिरमौर। एक रिफाइनरी का लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला है और खुशी की बात यह है कि इसका शिलान्यास हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा पुरुष, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। जिस काम को वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया, उस काम को परिपूर्ण करने का सौभाग्य मिले, इससे बड़ा जीवन का आनंद और क्या हो सकता है।

भाइयों-बहनों, यह ऐसी योजना है जिसके कारण यहां के लाखों नौजवानों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होने वाले हैं। और इसलिए यह पारादीप रिफाइनरी एक प्रकार से ओडिशा का विकासदीप है। यह पारादीप रिफाइनरी ओडिशा के नौजवानों का भाग्यदीप है। यह पारादीप रिफाइनरी हिन्दुस्तान की कोटि-कोटि गरीब महिलाएं, जो लकड़ी का चूल्हा जलाकर के खाना पकाती हैं, धुएं के कारण बच्चे बीमार हो जाते हैं, खुद बीमार हो जाती हैं। ऐसी गरीब माताओं को एक नई आशा जगाने वाली पारादीप रिफाइनरी है जहां से गैस सिलेंडर गरीब के घर तक पहुंचने वाले हैं।

सरकार जब काम करती है तो किस तेजी से कर सकती है, इसका उदाहरण आपने देखा है। हमारे देश के कई प्रोजेक्ट, 40-50 साल किसी को विचार आए, 10 साल के बाद कागज पर उतरे, और 5-10 साल बीत जाए योजना बनते-बनते, फिर शिलान्यास हो और उसको करते-करते तो पीढ़ियां बीत जाए, लेकिन वो काम पूरा नहीं होता है। आजकल मैं कहीं किसी योजना का उद्घाटन करने जाता हूं तो खासकर के हमारे कांग्रेस के मित्र तुरंत ब्यान देते हैं – ये तो हमारे जमाने में शुरू हुआ था। भाइयों-बहनों, अगर मेरे हाथ से किसी योजना का उद्घाटन करने का अवसर मिले, मुझे आनंद होगा स्वाभाविक है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के नाते मुझे आनंद नहीं होता है। मुझे तो आनंद तब होता कि यह काम अगर 15 साल पहले पूरा हो गया होता, यहां के लाखों लोगों को रोजगार मिला होता।

हमारे यहां योजनाओं को रुकावटें, विलंब, कभी कोर्ट-कचहरी, कभी टेंडर प्रक्रिया, कभी जन आंदोलन, न-जाने ऐसी-ऐसी मुसीबतों से गुजरना पड़ता है कि हमारी योजनाएं बहुत महंगी हो जाती हैं। देश के अंदर प्रगति करने के लिए देशवासियों ने, bureaucracy ने, उद्योग जगत ने, सामान्य नागरिकों ने, नीति निर्धारकों ने, एक ऐसे culture को जन्म देने की जरूरत है कि जहां योजनाएं समय पर शुरू हों, निर्धारित समय से आगे बढ़ें और निर्धारित समय में पूर्ण हो ताकि देश को उसका लाभ मिले, समय से पहले लाभ मिले।

भाइयों बहनों हम वो work culture पर लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कभी विलंब के कारण देश को गंभीर नुकसान न हो। भाइयों बहनों, इस रिफाइनरी में 78 करोड़ kg एलपीजी का निर्माण होने वाला है। 500 करोड़ लीटर पेट्रोल का उत्पादन होने वाला है। 660 करोड़ लीटर डीजल का उत्पादन होने वाला है। केरोसीन और एटीएफ मिला करके दो सौ पचास करोड़ लीटर का उत्पादन होने वाला है। 27 लाख क्विंटल सल्फर का उत्पादन होने वाला है। 120 लाख क्विंटल पेट्रोलियम कोक निर्माण होने वाला है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इन सारे उत्पादनों के कारण देश के आर्थिक विकास में कितनी बड़ी गति आएगी।

हिंदुस्तान के पूर्वी छोर पर ओडिशा की धरती से कोई समय था भारत की पहली सूरज की किरण यहां आती थी अब भारत को नई ऊर्जा यहां से प्राप्त होने वाली है। यह ताकत पारादीप ने दिखाई है। भाइयों-बहनों इसके कारण लाखों नये रोजगार की संभावनाएं पैदा हुई हैं। इसमें से वो raw material तैयार होगा, उस raw material के कारण छोटे-छोटे प्लास्टिक के अनेक उद्योग लग सकते हैं। और उसके लिए skill development का काम सरकार कर रही है। मुद्रा योजना के द्वारा पैसे दे रही है। Start-up India, Stand-up India के लिए, नौजवानों को नया अविष्कार करके काम करने के लिए सरकार सहूलियत दे रही है। पारादीप रिफाइनरी इसके साथ एक विकास की पूरी लम्बी यात्रा चलने वाली है, जो ओडिशा का भाग्य बदलने का काम करने वाली है।

भाइयों-बहनों आज हमारे देश में लाखों गरीबों परिवार करोड़ों गरीब परिवार उनको खाना पकाना है तो लकड़ी का चूल्हा जलाना पड़ता है और लकड़ी के चूल्हे के जलने से वैज्ञानिकों का कहना है कि एक घंटा उस चूल्हे के धुएं में अगर कोई रहता है तो 400 सिगरेट पीने जितना धुआं उनके शरीर में चला जाता है। उन गरीब मां-बहनों की health का क्या होता होगा, उनके

स्वास्थ्य का क्या होता होगा। हमारी कोशिश है इन गरीब माताओं के पास एलपीजी का गैस सिलेंडर पहुंचे। वो लकड़ी के चूल्हे से, धुएं से मुक्ति पाएं। और यह पारादीप रिफाइनरी में इतनी बड़ी मात्रा में एलपीजी गैस का निर्माण होने वाला है कि वो संभव होगा।

भाईयों-बहनों हमारे देश के किसान को यूरिया चाहिए। fertilizer के लिए यूरिया चाहिए। यूरिया के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, उनमें एक चीज की जरूरत होती है गैस की। अगर पूरी मात्रा में गैस उपलब्ध हो, तो यूरिया का उत्पादन बढ़ता है। हमारे देश के किसान को समय पर यूरिया पहुंच सकता है। और इसलिए हम इसी पारादीप योजना के तहत आने वाले दिनों में पूर्वी हिंदुस्तान के विकास के लिए fertilizer के कारखानों को आरंभ करना चाहते हैं, ताकि इस इलाके के किसानों को आवश्यक मात्रा में यूरिया मिले। हमारे देश में आने वाले दिनों में ऊर्जा के इन क्षेत्रों में किसानों की भलाई के लिए हमने एक ओर योजना बताई है। यह बात सही है कि रिफाइनरी की जरूरत है, रिफाइनरियां बढ़नी भी चाहिए। हम चाहते हैं कि विदेशों से जो हमें तेल आयात करना पड़ रहा है उसमें कमी कैसे लाएं। मैंने सरकार के अधिकारियों की एक दिन मीटिंग की। मैंने उनसे कहा जब देश आजाद हो करके 75 साल मनाएगा, 2022 में हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। मैंने कहा कि जब आजादी के 75 साल हम मनाएंगे, तब आप यह जो विदेशों से हमें oil लाना पड़ता है, उसमें 10 प्रतिशत कमी कर सकते हो क्या? मैंने उनके सामने चुनौती रखी है। और मुझे विश्वास है कि हमारी oil कंपनियां, हमारा पेट्रोलियम डिपार्टमेंट पूरी ताकत लगा करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाएंगे। अभी जो हमारा oil आता है, वो ज्यादातर खाड़ी के देशों से आता है। लेकिन हमारा सपना है खाड़ी का भी तेल हो, झाड़ी का भी तेल हो। खाड़ी का तेल और झाड़ी का तेल उसको हमने मिलाना है। और इसलिए हमने कहा है कि हमारे देश के किसान जो गन्ने की खेती करते हैं और उस गन्ने के रस में से एथेनोल बन सकता है। जितनी चीनी की जरूरत है, sugar की जरूरत है, उतनी sugar बनाए और जो अतिरिक्त sugar cane से एथेनोल बनाएं। और यह एथेनोल का हमारे पेट्रोलियम पैदावर के बीच मिक्स करें, ताकि हमारी गाड़ियां भी तेज चलें और पर्यावरण की भी रक्षा हो और देश में बहुत बड़ी मात्रा में यह झाड़ी का तेल का एथेनोल sugar cane से निकालने वाला process करके बनाया गया, उसकी प्रकार से मेरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुत बड़ी मात्रा में जट्रोफा की खेती करते हैं। हमारे पड़ोस में ओडिशा के जट्रोफा से भी जो तेल निकाला जाता है वो तेल भी हमारी पेट्रोलियम पैदाइशों की आवश्यकता में जुड़ सकता है। हम झाड़ी के तेल की तरफ भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सोलर एनर्जी पर बल दे रहे हैं, ताकि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनें। भारत अपने पैरों पर खड़ा हो, दुनिया में किसी पर आश्रित न रहना पड़े। यह पारादीप रिफाइनरी उस काम को बल देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम इस सरकार के द्वारा उठाया गया है।

भाईयों-बहनों हमारे देश में किसी भी किसान परिवार को पूछोगे, सौ एकड़ भूमि होगी। उसके बाद भी अगर किसान को पूछोगे कि आपके तीन बेटे हैं क्या सोच रहे हो बेटों को आगे कहां ले जाना चाहते हो, तो किसान बाप कहता है एक बेटे को तो खेती में लगाऊंगा, लेकिन दो बेटे उनको तो शहर में भेज दूंगा वो अपना रोजी-रोटी कमा लेंगे, वहां कई नौकरी-धंधा कर लेंगे। यानी किसान भी अपने तीन बेटों को अब खेती में लगाना नहीं चाहता। किसान भी अपने एक बेटे को खेती दे करके दो बेटों को किसी दूसरे काम में लगाना चाहता है। यह दूसरा काम किसान के बेटे को कब मिलेगा। क्या किसान का बेटा बेरोजगार रहे, क्या किसान का बेटा कर्जदार बनता चले, अगर हमारे गांव के किसान के बेटे को भी रोजगार देना है तो हमारे देश में हमें उद्योगों को बढ़ावा देना होगा।

अगर यह पारादीप रिफाइनरी न बनती। यह तीन हजार एकड़ भूमि अगर इस काम के लिए न लगाई गई होती, तो लाखों लोगों को रोजगार के अवसर पैदा नहीं होते। पूरे ओडिशा के भाग्य बदलने में हमें यह जमीन काम न आती। यह पारादीप रिफाइनरी है, जिसके कारण यह ज़मीन आज हिंदुस्तान के गरीब किसान के बेटे को रोजगार देने का कारण बन रही है। और

इसलिए भाइयों बहनों हम नौजवानों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़े। क्योंकि हिंदुस्तान जवान हैं, दुनिया का सबसे जवान देश हिंदुस्तान है।

65 प्रतिशत जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है। जिस देश के पास इतने जवान होते हैं, उस देश के सपने भी जवान होते हैं, उस देश के इरादे भी जवान होते हैं। उस देश के संकल्प भी जवान होते हैं और उस देश को आगे बढ़ाने के लिए ताकत भी लगती है, वो जवान ताकत होती है, जो भारत के भाग्य को बदलती है। और इसलिए हमने मुद्रा योजना के द्वारा नौजवानों को अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अवसर मिले। हम नहीं चाहते कि हमारे देश का नौजवान Job Seeker बने, Job पाने के लिए बेचारा इधर-उधर भटकता रहे, हम चाहते हैं ऐसा माहौल कि हमारा देश का नौजवान Job Seeker नहीं, Job Creator बनें। एक को, दो को, पांच को रोजगार दें, ऐसी नौजवान को ताकत मिले। और इसलिए मुद्रा योजना के तहत बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि आज नौजवानों को देने की दिशा में हमने कदम उठाया है।

करीब-करीब एक लाख करोड़ रुपया पिछले दिनों हमने दिया है। इतने कम समय में देश के सामान्य परिवार के लोगों को एक लाख करोड़ रुपया मुद्रा योजना में मिलना कोई छोटी बात नहीं है। मुझे अभी धर्मेद जी बता रहे थे कि पूरे ओडिशा में पिछले 60 साल में 26 लाख लोगों को गैस सिलेंडर मिला। 60 साल में 26 लाख। धर्मेद्र प्रधान जी मंत्री बनने के बाद एक साल के भीतर-भीतर 11 लाख गरीब परिवारों में गैस का सिलेंडर अकेले ओडिशा में पहुंचा दिया। काम तेज गति से कैसे होता है, इसका यह उदाहरण है। 60 साल में 26 लाख, एक साल में 11 लाख, यह काम किया जाता है, यह काम यह सरकार कर रही है और इसलिए हमारी कोशिश है कि हमारे देश के नौजवानों को रोजगार की नई संभावनाएं पैदा हों। अब तक हमारे देश के अर्थ कारण की पंडित लोग चर्चा करते हैं तो दो बातें हमेशा कहते हैं। बड़े-बड़े अर्थशास्त्री जो लिखते हैं, वो कहते हैं एक पब्लिक सेक्टर, दूसरा कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। मैं तीसरे सेक्टर पर बल दे रहा हूं। Economy में अगर पब्लिक सेक्टर का महत्व है, प्राइवेट सेक्टर का महत्व है तो तीसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र को भी बल देने की जरूरत है। वो है personal सेक्टर। एक – एक individual स्वयं बलबूते पर खड़ा होकर के आगे बढ़े और इसलिए एक-एक व्यक्ति को आगे बढ़ाना, एक-एक परिवार को आगे बढ़ाना। उस प्रकार की आर्थिक नीतियों को बल देकर के यह सरकार आगे बढ़ रही है।

भाइयों-बहनों, मुझे हमारे वैज्ञानिकों को, हमारी युवा पीढ़ी को आज विशेष रूप से बधाई देनी है और वो बधाई है - पारादीप रिफाइनरी में 'मेक इन इंडिया' का एक नया रिकॉर्ड प्रस्थापित कर दिया। इस क्षेत्र में दुनिया के कई देश आगे हैं, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने Indmax की जो योजना थी और raw material में से process करने की technique में भारत के वैज्ञानिकों द्वारा, भारत में बना हुआ, भारत के टैक्निशियनों द्वारा निर्मित किया गया प्रोजेक्ट, आज पारादीप में लगा है।

दुनिया के लोगों को अचरज हो रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में outcome देने वाला, इतनी तेज गति से outcome देने वाला, इतना perfect process करने वाला, इतनी बारीकी से हर element का division करने वाला, यह technology develop करने के लिए पूरे विश्व के technician, वैज्ञानिकों को भारत ने अचंभे में डाल दिया है और यह काम यह पारादीप रिफाइनरी में हो रहा है।

पूरी तरह Indigenous technology का उपयोग करके और उसके कारण LPG के उत्पादन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। हमारी economy को कम खर्च में ज्यादा बल देने का कारण बनने वाली है। और इसलिए भाइयों-बहनों, वे सभी वैज्ञानिक, वे सभी technician भी इस बात के लिए अभिनंदन के बहुत-बहुत अधिकारी हैं। मैं श्रीमान धर्मेन्द्र प्रधान जी को, उनकी पूरी टीम को इस काम को तेज गति से आगे बढ़ाकर के 18 महीने के भीतर-भीतर पूर्णता पर पहुंचाने के लिए हृदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूं, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं। उनका साधुवाद करता हूं।

भाइयों-बहनों, यह पारादीप, ऐसा दीप प्रज्ज्वलित हुआ है जो विकास की नई संभावनाओं को लेकर के आया है। सदियों पहले, ओडिशा स्वर्णिम युग का कालखंड रहा है। यह पारादीप के बाद ओडिशा में फिर से एक बार उज्ज्वल भविष्य का कालखंड प्रारंभ हो रहा है और भारत सरकार इस काम के लिए जितना करना होगा, कभी पीछे नहीं हटेगी।

भारत सरकार की पूरी मदद रहेगी क्योंकि ओडिशा के नौजवान हिन्दुस्तान का भाग्य बदलने के लिए है। उनको अवसर मिलना चाहिए और अवसर उपलब्ध कराने का काम यह सरकारी कर रही है।

मेरी आप सब को बहुत-बहुत शुभकामनाएं है। फिर एक बार आप सब को,

जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ , जय जगन्नाथ।

हिमांशु सिंह / तारा / मनीषा

**Press Information Bureau
Government of India
Prime Minister's Office**

05-February-2016 16:02 IST

Text of PM's Speech at the inauguration of BPCL at Lepetkata in Dibrugarh, Assam

श्रीमान तरुण गोगोई जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी और भारी संख्या में उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों

आज डिब्रूगढ़ में दो महत्वपूर्ण projects का लोकार्पण हो रहा है। और यह महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि इसके अंदर प्राकृतिक संपदा का Value Addition है और असम के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक-अनेक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इन दो projects के कारण पूरे हिंदुस्तान में स्वाभाविक आनंद है तो असम में सर्वानंद है। क्योंकि ये राष्ट्र की विकास यात्रा में बल देता है। अब सचमुच में तो इस projects के उद्घाटन का अवसर मुझे मिलना ही नहीं चाहिए था। अगर ये इकाई आज से 25 साल पहले हो गई होती उस समय के प्रधानमंत्री को इसका अवसर मिला होता, तो यहां पर इतने नए-नए उद्योग आए होते, यहां इतने लोगों को रोजगार मिला होता, और पिछले 25 साल से यहां सर्वानंद का माहौल होता।

लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है बहुत सारे अच्छे काम, उसको पूरा करना ये शायद मेरे ही सौभाग्य में लिखा हुआ है। हमारे देश में एक सबसे बड़ी चुनौती यह है, हम योजनाओं को समय से पहले सोच नहीं पाते हैं, अगर मजबूरन सोचते हैं तो योजना परिपूर्ण करने का रोडमैप नहीं बना पाते, फिर भी अगर हो गया तो घोषणा करते हैं, घोषणा करने के बाद सालों-साल शिलान्यास के लिए इंतजार होता है, शिलान्यास होने के बाद पूर्ण होने में सालों लग लाते हैं और बाद में लोग भूल जाते हैं तब जा करके उद्घाटन की नौबत आती है। और उसके कारण जिस काम की लागत 500 करोड़ होनी चाहिए वो 1000-1100 करोड़ तक पहुंच जाती है। और इतने विलंब के कारण देश के अर्थकारों को जो नुकसान होता है, उसका का तो कोई हिसाब ही नहीं है। अगर आज यही projects ही 25 साल पहले पूरा हुआ होता और 25 साल पहले उसका उद्घाटन हुआ होता, तो शायद आज यहां पर दूसरी पीढ़ी के लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया होता, एक पूरी पीढ़ी बेचारी चली गई। और इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि विचार किसी को भी आया हो, सपना किसी को भी आया हो, शिलान्यास किसी ने भी किया हो, लेकिन देश का भला उसमें है, कि हम इन सारी चीजों को परिपूर्ण करें और लोगों के सपनों को साकार करें। और इसलिए मैं भारत सरकार में एक प्रगति कार्यक्रम चलाता हूं आजकल। और राज्यों के मुख्यसचिवों के साथ video conference से खुद बात करता हूं, और ऐसे जो अटके पड़े projects हैं, किसी न किसी कारण से रुके पड़े हैं, ऐसे stalled projects को गति देने के लिए एक विशेष प्रयास करता हूं।

पिछले दिनों कुछ अखबारों ने लिखा था कि लाखों-करोड़ों के stalled projects अब उस कैदखाने से बाहर निकले हैं, और तेज गति से परिपूर्ण होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उसमें ये project भी है जिसका आज उद्घाटन संभव हुआ है। आने वाले दिनों में भी मेरा स्पष्ट मानना है कि भारत की अगर प्रगति करनी है, तेज गति से प्रगति करनी है, समय रहते अगर प्रगति करनी है, तो भारत का सर्वांगीण विकास होना चाहिए।

ऐसा नहीं हो सकता है कि हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर जो है, उसका तो विकास हो, केरल में हो, कर्नाटक में हो, गोवा में हो, महाराष्ट्र में हो, राजस्थान में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, जम्मू कश्मीर में हो लेकिन हिंदुस्तान का जो पूर्वी

छोर है, उड़ीसा हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, आसाम हो, नॉर्थ-ईस्ट के अन्य राज्य हों, का विकास नहीं होगा तो हिंदुस्तान का विकास अधूरा रहेगा। और इसलिए भारत के पूर्वी छोर का विकास, इस पर सबसे ज्यादा बल देना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और तभी जाकर के भारत का संतुलित विकास होगा, भारत का सर्वांगीण विकास होगा। और इसलिए हमने Act East Policy बनाई है। और इस Act East Policy को न सिर्फ हिंदुस्तान का पूर्वी इलाका लेकिन हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके के साथ सटे हुए देश जिनके साथ सहज रूप से हमारे व्यापारिक संबंध यहां से विस्तृत हो सकते हैं, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे सिंगापुर, मलेशिया हो, उधर इंडोनेशिया हो, ये सारे देश हमारे इस भूभाग के विकास के साथ उनकी connectivity बहुत बड़ी ताकत देती है। और इसलिए लगातार भारत इन देशों के साथ भी उन कामों को बल दे रहा है, infrastructure को बल दे रहा है, कि जिसके कारण भारत का ये जो नॉर्थ-ईस्ट इलाका है, भारत का जो पूर्वी इलाका है, उसमें एक नई विकास की दुनिया खड़ी हो जाए और उसी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं।

भारत की आजादी के बाद कभी भी सोचा न गया हो, दिया न गया हो, इतना रेलवे का बजट नॉर्थ-ईस्ट के लिए लगाया है। क्योंकि अगर रेलवे infrastructure बनता है तो पूरा नार्थ ईस्ट सहज रूप से हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाता है। नार्थ ईस्ट के पास अपार संभावनाएं हैं, लेकिन connectivity के आभाव में उसकी विकास यात्रा रुक जाती है। यहां के नौजवान होनहार हैं। सामर्थ्यवान हैं, बुद्धिमान है, अगर उनको अवसर मिल जाए तो आसाम को हिंदुस्तान का नंबर एक राज्य बनाने की ताकत रखते हैं।

ये polymer का उद्योग एक प्रकार से value addition है। भारत को जो विदेशों से लाना पड़ता है, उसमें थोड़ी बचत हो जाएगी और उसके अंदर मूल्यवृद्धि के कारण छोटे छोटे कारखाने लग सकते हैं। आज प्लास्टिक का युग तो है में मानना पड़ेगा लेकिन दुनिया प्रति व्यक्ति जो प्लास्टिक की खपत है उसकी तुलना में भारत की बहुत कम है। प्रति व्यक्ति मुश्किल से दस kg है। अगर विश्व के सामान्य औसत से मिलाना है तो यहां पर प्लास्टिक उद्योग के लिए बहुत संभावनाएं बढ़ी हैं। जीवन की बहुत-सी आवश्यकताएं अब प्लास्टिक के बलरूप में साकार हो रही हैं। यहां पर raw material उपलब्ध हो, और यहां के नौजवान में skill हो, छोटा-छोटा कारोबार चालू करे, एक पूरा औद्योगिक विस्तार खड़ा हो जाएगा। लाखों नौजवानों को यहां रोजगार मिलेगा और इसके लिए हमने मुद्रा योजना को भी आरंभ किया है। Start-up India , Stand-up योजना को आरंभ किया है। यह दोनों योजनाएं ऐसी है कि इस उद्योग से जो raw material निकलेगा, उसके value addition के लिए जो काम करना चाहता है उसे मुद्रा से पैसा भी मिलेगा और Start-up India , Stand-up योजना का लाभ उसकी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। इसमें काफी concession है। बहुत सारे incentives हैं। और मैं आशा करूंगा कि असम के नौजवान इसके साथ जुड़े हुए उद्योग लगाने के लिए आगे आएंगे। और मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा, डिपार्टमेंट से कि यहां जो raw material निकलेगा, जिसका value addition होगा, उसको सबसे पहले आसाम के नौजवानों को मौका दिया जाए और वे अगर उपयोग करते नहीं है तो अब जा करके हिंदुस्तान में और भाग में ले जाया जाएगा।

इतना बड़ा निर्णय आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा आपका भाग्य बदल सकता है। लेकिन हमारी प्राथमिकता है आसाम और नॉर्थ ईस्ट, हमारी प्राथमिकता है यहां पर विकास। आज किसी भी किसान परिवार में जाइए और उस परिवार में अगर तीन बेटे हैं, और किसान को पूछो 100 एकड़ भूमि होगी उसको पूछो भाई बच्चों के लिए क्या सोचा है तो किसान कहता है एक बेटे को तो खेती में लगाऊंगा, लेकिन दो बेटों को कहीं शहर में भेज करके नौकरी पर लगा दूंगा ताकि उनका गुजारा चल जाए। यानी हर किसान अपने तीन बेटों में से दो को किसी कारखाने में, कहीं नौकरी पर लगाना चाहता है। किसान के इन दो बेटों को रोजगार कब मिलेगा। क्या किसान का एक बेटा तो कमाएगा और दो बेटे भूखे रहेंगे? अगर किसान के एक बेटे के लिए खेती है दो बेटे के लिए रोजगार के लिए उद्योग लगाना अनिवार्य है, आवश्यक है। और इसलिए गांव का अगर भला करना होगा तो किसान के संतानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। और उसके लिए बड़े-बड़े शहरों में उद्योग

लगेगे तो काम नहीं होगा। डिब्रूगढ़ छोटे-छोटे स्थान पर भी हमें उद्योगों के लिए जाल बिछाने पड़ेंगे।

और हमारी सरकार की कोशिश है कि छोटे-छोटे स्थान पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। उद्योगों का अवसर उपलब्ध कराना। मूल्यवृद्धि हो, value addition हो, ताकि देश की आय बढ़े। उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से प्राकृतिक संपदा की मूल्यवृद्धि की अनिवार्यता है वैसे भी व्यक्ति के जीवन की भी मूल्यवृद्धि होनी चाहिए। unskilled labour कम कमाता है, Skilled labour ज्यादा कमाता है और इसलिए हम Skill development पर बल दे रहे हैं। हर नौजवान के हाथ में हुनर होना चाहिए। Skill होना चाहिए और Skill के भरोसे वो अपने लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकता है और उसकी एक मांग भी बढ़ने वाली है और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं।

भाईयों-बहनों आने वाले दिनों में विकास की इस यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ाना है। भारत सरकार cooperative federalism को लेकर केंद्र और राज्य मिल करके देश को आगे बढ़ाये, इस मंत्र को ले करके, सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को ले करके अभिरथ प्रयास कर रहा है।

आने वाले दिनों में उसके फल भी आपको मिलेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। मैं फिर एक बार आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं और राष्ट्र के चरणों में धरोहर जहां एक जगह पर polymer तैयार होगा तो दूसरी जगह पर wax का काम होगा और दोनों हमें बाहर से लाने पड़ते हैं उसमें कमी आएगी और देश की आवश्यकता की पूर्ति में यह भी अपना योगदान देंगे। मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं बहुत-बहुत धन्यवाद।

अतुल तिवारी, हिमांशु सिंह, सोनिका, निर्मल शर्मा

**Press Information Bureau
Government of India
Prime Minister's Office**

23-March-2016 11:28 IST

Text of PM's statement at the inauguration of India-Bangladesh Power Grid Transmission Line

मेरी दृष्टि से यह एक ऐतिहासिक अवसर है। शायद दुनिया में बहुत कम ऐसे अवसर आते होंगे कि आधुनिक विज्ञान के माध्यम से दो देश के प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री के साथ मिल करके किसी योजना का लोकार्पण करते हों। इस दृष्टि से यह एक बड़ा यह महत्वपूर्ण मैं अवसर मानता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने अपने अभिभाषण के माध्यम से उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया, हौसला बढ़ाया मैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान जी का भारत के साथ नाता बड़ा अटूट रहा। आपने भी उन संकट के दिनों में मानवता के उस काम में भारत किस प्रकार से आपके दुख दर्द का भागीदार बना इसको हमेशा याद किया है और भारत के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। आज भी उस भावनाओं को उसी तीव्रता के साथ आप प्रकट कर रही है।

वो दिन थे जब दुख, दर्द और पीड़ा से भरा बंगलादेश था। आज बंगलादेश ऊंचाईयों की ओर जा रहा है। तब भी हम कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ चल रहे हैं, आप हमारे साथ चल रहे हैं। हम दोनों मिल करके दुनिया के सामने एक मिसाल रख रहे हैं कि पड़ोसियों के साथ संबंध किस प्रकार के हो सकते हैं। Inter dependent world को साकार करने के उत्तम से उत्तम मार्ग कौन से हो सकते हैं और मैं देख रहा हूँ कि एक के बाद एक सहयोग के सहयोग के हमारे प्रयास बहुत ही उत्तम प्रकार के परिणाम देने का सामर्थ्य रखते हैं। और मैं इस अवसर को उस रूप में देखता हूँ और मुझे विश्वास है कि ग्लोबल community एक छोटे से कमरों में वीडियो कैमरा के द्वारा हो रहे इस कार्यक्रम को एक वैश्विक स्तर पर भी इस घटना को देखेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।

आज की घटना- बिजली भारत से बंगलादेश जा रही है। एक नई ऊर्जा, विकास की ऊर्जा का यह अवसर है। दूसरी तरफ हमारे पास एक ऐसा गेटवे खुल रहा है। क्योंकि अब तक हमारा डिजिटल वर्ल्ड में एंट्री के जो दो हमारे गेटवे थे, वो एक पश्चिम में था एक दक्षिण में था। लेकिन हमारा पूरब अछूता था। और मैं Act East पॉलिसी को ले करके चल रहा हूँ तब मेरे लिए यह पूरब का गेटवे बहुत महत्वपूर्ण है। और बंगलादेश के साथ मिल करके डिजिटल वर्ल्ड का पूरब का गेटवे खुलना यह अपने आप में, भारत के पूर्वी इलाके में और विशेषकर असम, नॉर्थ ईस्ट including त्रिपुरा और सिक्किम यह हमारा जो अष्ट लक्ष्मी का प्रदेश है। वहां के नौजवानों के लिए यह एक नई चेतना जगाने वाला अवसर बनने वाला है। और आज की दुनिया communication की ताकत पर चलती है। communication की ताकत को बढ़ावा देने का यह अवसर है। और इसलिए आपने हमें जो सहयोग दिया, जो सुविधा दी उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

आने वाले दिनों में बिजली के संबंध में भी जो transmission लाइनें डाली जा रही हैं हमने पहले से ही उसकी capacity ज्यादा रखी है ताकि आने वाले दिनों में जैसी उसकी आवश्यकता पड़े और हम जितना ज्यादा आपके साथ मिलकर के ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर सकें। हमारा निरंतर प्रयास रहेगा और मैं आज के इस अवसर पर, मैं इसको बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूँ और कुछ दिन पहले हमने Road connectivity का सफल प्रयास आगे बढ़ाया बांग्लादेश, नेपाल, भारत और भूटान। आज हम बिजली के माध्यम से एक नई ऊर्जा दे रहे हैं और हम 21 वीं सदी की महत्वपूर्ण connectivity वो digital connectivity को जोड़ रहे हैं। यानि जल हो, थल हो, नभ हो। अब बांग्लादेश और भारत जुड़ते ही चले जा रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर के आगे चले जा रहे हैं और जैसा मैंने आकर के कहा था।

अब हमें Space में भी आगे साथ-साथ बढ़ना है। बंग-बंधु Satellite, भारत की दिली इच्छा है कि बंग-बंधु Satellite में

भी जैसे Road में भी हम आपके साथ जुड़े हैं, जैसे जल में हम आपके साथ जुड़े हैं, जैसे Digital दुनिया में हम आपके साथ जुड़े हैं, Space में भी आपके साथ जुड़कर के आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं फिर एक बार आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से आज भारत होली का उत्सव मना रहा है। होली हमारे यहां एक बड़ा पवित्र त्योहार माना जाता है, बांग्लादेश में भी कुछ भू-भाग है जहां पर होली का त्योहार मनाया जाता है और होली के इस पवित्र त्योहार पर ये अवसर अपने आप में हमारे संबंधों को नए रंगों से भर देगा और एक नई ऊर्जा और नई connectivity का कारण बनेगा।

आज एक और भी महत्वपूर्ण अवसर है और आज वो महत्वपूर्ण अवसर है बांग्लादेश और भारत T-20 का मैच आज है। मैं दोनों टीमों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भारत और बांग्लादेश जब खेलते हैं हमारे नौजवान तो sports का जय-पराजय से ऊपर उठकर के संबंधों में sportsman spirit की ताकत पैदा होती है। जैसे बिजली नई ताकत देती है, हमारी sportsman spirit भी नई ताकत देती है। आज उसी sportsman spirit के साथ हमारी दोनों टीमों खेलें और दुनिया के अंदर sportsman spirit का नजारा दिखाएं। मेरी दोनों टीमों को बहुत-बहुत शुभकामना है। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

हिमांशु सिंह/ तारा/ मुस्तकीम खान

**पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
प्रधानमंत्री कार्यालय**

30-अगस्त-2016 18:01 IST

गुजरात के जामनगर में सौराष्ट्र नर्मदा सिंचाई (SAUNI) परियोजना के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित जनसभा को दिए गये प्रधानमंत्री के संबोधन का हिंदी अनुवाद

**भारत माता की जय,
भारत माता की जय।**

यहां उपस्थित मेरे प्यारे भाईयों और बहनो,

दाहोद जिला आदिवासी जिला है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। अगर सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में गुजरात की भूमिका पर चर्चा करनी हो, तो हमें इसका प्रारंभ दाहोद से करना पड़ेगा। हमने स्वतंत्रता संग्राम को, आजादी के जंग को इतना सीमित कर दिया है कि हम आजादी की लड़ाई लड़नेवाले आदिवासी भाईयों-बहनो को भूल गये। दोस्तो, इस देश के हर गांव ने, लाखों लोगो ने, सौ-सौ साल तक आजादी के लिये अविरत त्याग और बलिदान की मशाल को प्रज्ज्वलित रखा। हिंदुस्तान का एक भी आदिवासी क्षेत्र ऐसा नहीं कि जिसने अंग्रेजो के ईंट का जवाब पत्थर से न दिया हो। पिछले थोड़े समय से लोग बिरसा मुंडा के नाम से परिचित हो रहे हैं। हमारे गुरु गोविंद ने आजादी के लिये कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी। इसी भूमि पर आजादी के लिये जंग हुआ था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में संपूर्ण दाहोद क्षेत्र में, उसके आदिवासीओ भाईयो और बहनो, अंग्रेजो के लिये सबसे बड़ी चुनौती बन गये थे। जब आज हम आजादी के 70वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहे हैं, तब आजादी के जंग में शामिल हुए आदिवासी योद्धाओ को, स्वतंत्रता सेनानीओ को, मैं आदिवासीओ की इस पवित्र, पावन भूमि पर से शत शत नमन करता हूँ।

भाईयों और बहनो, 1960 में गुजरात की रचना हुई। जब बृहद् महाराष्ट्र में से अलग राज्य के तौर पर गुजरात की रचना हुई, तब ये चर्चा आम थी की गुजरात के पास पानी नहीं है, गुजरात के पास अपने उद्योग नहीं हैं, गुजरात के पास खनीज नहीं हैं, ये राज्य खतम हो जायेगा। गुजरात अपने पैरो पर कभी खड़ा नहीं हो पायेगा - ये आम धारणा लोगो के दिमाग में घर कर गई थी। महागुजरात के आंदोलन के सामने ये सबसे बड़ा तर्क था। आज, भाईयो और बहनो, संपूर्ण राष्ट्र को गुजरात पर गर्व है के इस राज्य ने, राज्य के लोगो ने, अनेक चुनौतीओ के बीच, मुश्किलों का सामना करते हुए, कुदरती संसाधनों की मर्यादा के बीच, हर चुनौती को ललकारा, हर चुनौती को चुनौती दी और एक के बाद एक सफलता अर्जित की, विकास के नये मापदंड प्रस्थापित किये। हमने चुनौती का सामना किया और सफल प्रयोग कर दिखाया।

जल की कमी हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी। जहां जल पहुंचा, वहां के लोगो ने अपनी ताकात का परिचय दिया। हमारे गुजरात के पूर्व क्षेत्र, आप ऊंमरगांव से अंबाजी तक देखो, आप को पथरीली जमीन, छोटे छोटे पर्वत दिखायी देंगे। इसलिये बारिश होती है, जल मिलता है, लेकिन बह जाता है। जल का संचय नहीं होता, जमीन में जल का संग्रह नहीं होता। इसलिये मेरे आदिवासी भाईयो को अपनी जमीन जल से नहीं, पसीने से सिंचनी पड़ती थी। रोजीरोटी के लिये उसे हिजरत करनी पड़ती थी। 40 से 50 डिग्री से तापमान में आसमान से आग बरसती है और इस आग में आदिवासी भाईयों को गांवों के मार्ग बनाने पड़ते थे। उनके पैरो में छाले पड़ जाते थे। इस तरह जीवन पसार होता था। इस स्थिति में हमने दूरदर्शी अभिगम अपनाया और जल को, पानी का समस्या के समाधान को प्राथमिकता दी। गुजरात सरकार का सबसे ज्यादा बजट पानी पर खर्च होता था और आज मुझे खुशी है के पानी की समस्या का समाधान हुआ है। आज एक के बाद एक लोकार्पण या शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हजारो करोडो रुपये, ये कोई मामूली रकम नहीं है, हजारो करोडो रुपये पानी की समस्या का समाधान करने के लिये खर्च किये गये। एक दशक पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि आदिवासी के रसोईघर के नल में पानी आयेगा ! हमने अभियान शुरू किया, क्योंकि समाज के सबसे नीचले पायदान पर स्थित इन्सान को शक्ति, सामर्थ दिया जाये, तो वो तेजी से प्रगति करता है। इतना ही नहीं, अपने साथ अपने जैसे, अपने समाज के, अपने साथीदारो को भी अपने साथे जोड़ने का प्रयास करता है।

जब से दिल्ली में हमारी सरकार बनी है, तब से हमने अभी तक उपेक्षित चीजों पर ध्यान केन्द्रित किया है। बैंक होती थी, लेकिन उसमें गरीबो के लिये प्रवेश वर्जित था। विविध बीमा योजना थी, लेकिन उसका लाभ गरीबो को नहीं मिलता था।

अस्पताले थी, लेकिन गरीबों को तो उसके दरवाजे के बहार ही खड़ा रहेना पड़ता था। बीजली का उत्पादन होता था, लेकिन आजादी मिलने के 70 वें साल में भी 18000 गांवों के लोग 18 वीं सदी जैसी स्थिति में जीने के लिये मजबूर थे। उन्होंने ने कभी बीजली देखी ही नहीं थी। इससे ज्यादा बदतर स्थिति और क्या हो सकती है! इसलिये भाईयों और बहनो, जब आपने, इस देश के एनडीए के सांसदों ने, इस धरती के लाल को, जिसको आपने बड़ा किया है, जिसका लालनपालन आपने किया, जिसको आपने संभाला, उसको इस देश के प्रधानसेवक के तौर पर, प्रधानमंत्री के स्वरूप में चुना, तब संसद में मेरे सर्वप्रथम प्रवचन में मैंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार है, मेरी सरकार दलितों, पीड़ितों, वंचितों की सरकार है। अगर हमारे समाज का यह बड़ा वर्ग, अगर विकास की मुख्य धारा में आये तो देश विकास की नई परिभाषा गढ़ सकता है। इस देश के किसानों को क्या चाहिये? इस देश के किसान को पानी मिले, तो वह मिट्टी में से सोना पैदा करने की कुव्वत रखता है। इसलिये प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत हमने अभियान शुरू किया है, एक भूगौरव कार्य का प्रारंभ किया है। हम लाखों करोड़ों रुपये के खर्च पर आनेवाले सालों में इस देश के एक-एक गांव तक पानी पहुंचाना चाहते हैं। पहले कहा जाता था कि इस देश के किसानों की, गरीबों की तीन आधारभूत आवश्यकता है - बीजली, पानी और सड़क। हमने उसमें और दो चीजों को जोड़ दिया - शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर इस पांच चीज को प्राथमिकता दी जाये और उसे सर्वसुलभ किया जाये, तो रोजगार अपने आप पैदा होगा और भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिये मजबूत आधार का निर्माण होगा। इसलिए आज हिंदुस्तान के कोने कोने में एक ही मंत्र गूंज रहा है - सबका साथ, सबका विकास। हम उस मंत्र को लेकर विकास को नयी ऊंचाई पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।

हमने देखा है कि कई राज्यों में सरकार बनती है और आते ही 100, 200 या फिर 500 करोड़ रुपये की योजना का जोरशोर से ढंढेरा पिटा जाता है। अखबारों की हेडलाइन बन जाती है। राज्य की जनता भी इस पर चर्चा करती है। अच्छी बात है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कई योजना सरकार के खजाने को भर देती है। राज्य सरकार के खजाने को ही नहीं, महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्राम पंचायत - सभी का खजाना भर जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री श्री विजयभाई एलईडी बल्ब की बात कर रहे थे। ये दिखने में बहुत छोटी बात लगती है। गुजरात ने दो-तीन माह से एक अभियान हाथ पर लिया है। गुजरात ने सवा दो करोड़ एलईडी बल्ब प्रस्थापित करके एलईडी बल्ब के मामले में हिंदुस्तान में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। मुद्दा बल्ब का नहीं है, बात फायदे की है। आप को पता नहीं है कि एलईडी बल्ब के उपयोग से गुजरात सालाना 1000 करोड़ रुपये की बचत करेगा। ये रुपये का इस्तमाल गरीबों के कल्याण के लिये होगा। इस खजाने का उपयोग किस तरह करना है उसका निर्णय राज्य सरकार कर सकती है, महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्राम पंचायत कररी सकती है। संपूर्ण योजना के केन्द्र में गांव है, गरीब है और किसानों का कल्याण है।

अब वनबंधु कल्याण योजना की बात करते हैं। दशकों में रु। 9000 करोड़ और एक दशक में 60,000 करोड़ रुपये। हमने एक दशक में 60,000 करोड़ रुपये आदिवासीओं पर खर्च करने की योजना बनाई है, क्योंकि हमें इस देश के आदिवासीओं का पुनरोत्थान करना है। वनबंधु कल्याण योजना इसी मनोमंथन का परिणाम है। इस योजना के द्वारा एक प्रयोग हो रहा है, जिसकी शुरुआत गुजरात में से हुई थी। आज ये प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में श्रीमान जशवंतसिंह भाभोर के नेतृत्व में हो रहा है। ये योजना सफल पुरवार होगी, इस का फायदा होगा - ये विश्वास भी लोगों में पैदा हुआ है।

भाईयों और बहनो, जब दाहोद में मैं संगठन का कार्य करता था, तब सामान्यतः स्कूटर पर घूमता था। आज हमारे बीच उपस्थित कई लोगों के घर में मैंने चाय पी है, भोजन किया है। उस वक्त जब मैं स्कूटर लेकर निकलता था, तो लोग कहते थे के आप ज्यादा अंदरूनी विस्तार में मत जाये। कभी किसी दिन मुश्किल में पड़ जाओगे। वो मुझे रोकते थे। उस वक्त कभी मैं परेल जाता था, दाहोद में। परेल को देखके मैं सोचता था कि ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी को इसकी परवा नहीं है। ये बहुत बड़ा स्थान है, लेकिन लोग रोजीरोटी के तलाश में बहार निकल रहे हैं। अतीत में सरकारें बहुत योजना बनाती थी, लेकिन सिर्फ कागजों पर। कभी इसका अमल नहीं होता था। दोस्तों, परेल इस जिले की सबसे बड़ी ताकात है। परेल रेलवे स्टेशन की कायापलट करने के लिये हमने एक अभियान छेड़ दिया है। हमने बड़े पैमाने पर कार्य शुरू कर दिया है। मैं सोचता था कि दाहोद मेईन लाइन पर स्थित अति महत्वपूर्ण स्टेशन है, सरकार के पास सिस्टम है, लेकिन किसी को कुछ अच्छा करने की इच्छा ही नहीं। ये जनता की कमाई की बरबादी का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया था।

भाईयों और बहनो, योजना का अमलीकरण शुरू हो गया है। तीन चरण में संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होगा। आपकी आंखों के सामने परेल का रेलवे यार्ड रोजगारी के नए अवसर प्रदान करेगा, यहां के अर्थतंत्र में नया जोश आयेगा। मुझे मालूम है, दाहोद जिला का आदिवासी किसान प्रगतिशील है। वो परंपरा को छोड़ने का, नई तकनीक को गले लगाने का साहस रखता है। ज्यादातर गुजरात में खेतीबाड़ी शब्द का प्रयोग करता है। ऊंमरगांव से लेकर अंबाजी तक लोग खेतीबाड़ी शब्द का प्रयोग करते हैं। मुझे गर्व है कि दाहोद जिला के आदिवासी किसान ने खेत को 'फूलवाडी' में परिवर्तित कर दिया। आज दाहोद के खेतों में भातिभांति के पुष्पों की खेती होती है। दाहोद जिले के किसानों ने इसका नेतृत्व किया है। वो कृषि में आधुनिक तकनीक का इस्तमाल करता है। मकई की खेती में तो वो नंबर 1 है। दाहोद जिला के आदिवासी के पास जमीन कम होती है, लेकिन उसका हौंसला बुलंद होता है। वो बहार जाता है, नया शीखता है और फिर गांव आकर उसे आजमाता है।

भाईयों और बहनों, ऊंमरगांव से लेकर अंबाजी तक आदिवासी क्षेत्र तक पीने का पानी पहुंचाने का अभियान शुरू हो गया है, लिफ्ट इरिगेशन से सिंचाई व्यवस्था करनी है। अभी हम इस काम पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। भविष्य में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सोलर पम्प भी क्रांतिकारी है। इससे बीजली के लिये किसानों की सरकार निर्भरता का अंत आ जायेगा। सोलर पंप में सरकार निवेश करेगी। नूतन प्रयोग चल रहे हैं। सूरज की रोशनी के बल पर ये पम्प चलेंगे। अभी प्रयोग चल रहा है, लेकिन आनेवाले दिनों में एक बहुत बड़ी क्रांति होनेवाली है। इससे हम टपक सिंचाई तकनीक में भी अपनी परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर पायेंगे। इसका लाभ आदिवासी किसानों को आनेवाले दिनों में मिलेंगे, हिंदुस्तान के किसानों को मिलेंगे।

हम एक स्वप्न लेकर चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब 2022 में देश स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह का जश्न मनायेगा, तब हिंदुस्तान के किसानों की आय दुगुनी हो जाये। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने गुजरात के डेरी उद्योग के महाशयों को, जिनको दिलचस्पी हो, उनको दिल्ली बुलाया था। मैंने उनकी मुलाकात मेरे अफसरो से करवाई थी। मैंने उनको कहा की, हर गांव में मधुमक्खी का संवर्धन और शहद का उत्पादन किजिये। जैसे गांव में लोग दूध का केन लेकर आते हैं, उसी प्रकार लोग दूसरे छोटे केन में शहद लेकर आयेंगे। लोगों को दूध के साथ शहद की आय भी होगी। डेरी दूध के साथ शहद का प्रोसेसिंग भी करे। दुनिया में इसकी बहुत ज्यादा मांग है। गुजरात के किसानों को इसका फायदा मिल सकता है। आनेवाले दिनों में इसका बहुत बड़ा लाभ देश को मिलेगा।

भाईयों और बहनों, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, आज जमीन के जो टुकड़े दिये गये, ये बहनों सिर्फ तसवीर खिंचवाने नहीं आयी। गुजरात सरकार ने उनको जमीन के टुकड़े दिये हैं, कृषि के लिये। उस में सबसे पहले नाम मेरी आदिवासी बहनों का है। दूसरा नाम उनके पतिदेवों का है। सैंकड़ों सालों से आदिवासी जमीन के मालिक नहीं थे, आज एक आदिवासी माता जमीन की मालकिन बनी है और उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है!

भाईयों और बहनों, मैंने कई साल गुजरात में गुजार है, लेकिन कभी जन्मदिन नहीं मनाया। आज भी नहीं मनाता। लेकिन मेरी माता के साथ कुछ क्षण गुजारने का प्रयास अवश्य करता हूँ। मैंने मेरी माता के आशीर्वाद लिये हैं, लेकिन गुजरात सरकार मुझे मुफ्त में वापस लौटने देना नहीं चाहती थी। उनका आग्रह था कि आप जब गुजरात में आ रहे हो, तो थोड़ा वक्त हमें भी दिजिये। गुजरात सरकार ने दो बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। एक कार्यक्रम नवसारी में है, जो भारत सरकार का है। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आदिवासी भाईयों का आशिष मिला। पुराने दोस्तों को देखने का, मिलने का मौका मिला। आपने मेरा स्वागत किया, मेरा सन्मान किया, आशिष दिये, ढेर सारा प्यार दिया। मैं आपका ऋणी हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं गुजरात सरकार का आभारी हूँ। गुजरात विकास के नये मापदंड स्थापित करे, सिर्फ अपने लिये नहीं, संपूर्ण भारत के लिये और हमेशा नंबर 1 रहे। इसी शुभकामना के साथ...आपका धन्यवाद।

भारत माता की जय

भारत माता की जय

भारत माता की.जय

AKT/AK

**पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
प्रधानमंत्री कार्यालय**

10-अगस्त-2016 17:45 IST

कुडनकुलम परमाणु बिजली संयंत्र की पहली इकाई के समर्पण समारोह में प्रधानमंत्री का संबोधन

महामहिम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन,

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री माननीया जयललिता जी,

मंत्री सुषमा स्वराज जी,

मंत्री पोन राधाकृष्णन,

मेरे प्रिय मित्रो !

नमस्कार,

वनक्कम !

आज कादिन सचमुच एक विशेष दिन है।

आज महामहिम पुतिन और मुझे कुडनकुलम परमाणु बिजली संयंत्र की पहली इकाई को समर्पित करने का सम्मान प्राप्त हुआ है।

इस अवसर पर मैं विशेष रूप से राष्ट्रपति पुतिन की उपस्थिति के लिए उनका कृतज्ञ हूँ।

इस अवसर पर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता जी की उपस्थिति से भी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ।

मित्रो, कुडनकुलम परमाणु बिजली संयंत्र की पहली इकाई को समर्पित करना भारत-रूस संबंधों में एक अगले ऐतिहासिक कदम का प्रतीक है।

इसकी सफल समाप्ति न केवल हमारे विशेष और विशिष्ट रणनीतिक साझेदारी की शक्ति का एक अच्छा उदाहरण है, बल्कि यह हमारी मित्रता का एक उत्सव भी है।

और, यह इस क्षेत्र में हमारे सहयोग की एक शुरुआत भर है।

शायद यह आम लोगों की जानकारी में नहीं है कि 1000 मेगावॉट क्षमता वाले कुडनकुलम परमाणु बिजली संयंत्र की पहली इकाई भारत में विद्युत शक्ति की एक सबसे बड़ी इकाई है।

आने वाले वर्षों में, हम परमाणु बिजली के उत्पादन की एक महत्वाकांक्षी योजना को शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

केवल कुडनकुलम में ही, 1000 मेगावॉट क्षमता वाली पांच और अधिक इकाइयों की योजनाएं हैं।

इस क्षेत्र में सहयोग की कड़ी में, हम कई बड़ी परमाणु बिजली इकाइयां स्थापित करने की योजना बना रहे हैं।

मित्रो,

आज का आयोजन भारत और रूस के अभियंताओं, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों के समूह के लिए एक आनंददायक अवसर है।

मैं उनके समर्पण और कठिन परिश्रम को सलाम करता हूँ और उनके श्रम की सफलता पर उन्हें बधाई देता हूँ।

मित्रो,

व्यापक प्रौद्योगिकीय उन्नति और बढ़ती आर्थिक समृद्धि, मानव विकास की गाथा रही हैं।

किंतु, हम सभी जानते हैं कि हमारे पर्यावरण पर कुप्रभाव के बिना यह संभव नहीं हुआ है।

भारत के लिए मेरा एक दृष्टिकोण है, जहां हमारे आर्थिक विकास की उपलब्धियां धरती माता के प्रति सम्मानपूर्ण हों और जहां हमारे औद्योगिक विकास के ईजन स्वच्छ ऊर्जा द्वारा अधिकाधिक संचालित हों।

कुडनकुलम परमाणु बिजली संयंत्र की पहली इकाई भारत में स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में भारत के सतत प्रयासों की एक अन्य महत्वपूर्ण कड़ी है।

यह हरित विकास के लिए साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में हमारी संयुक्त प्रतिबद्धता का संकेत है।

महामहिम राष्ट्रपति पुतिन,

परमाणु बिजली उत्पादन के क्षेत्र में हमारे प्रयासों की सफलता हमारे सहयोग की एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है।

यह हमारे संबंधों को दुरुस्त और सतत बनाए रखने की दिशा में हमारे साझा संकल्प को दर्शाता है।

इनके अलावा, यह आपकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता, सतत समर्थन और हमारे संबंधों के मूलविषय और विशेषता में सुधार लाने की दिशा में आपके सशक्त नेतृत्व को दर्शाता है।

इसके लिए मैं महामहिम राष्ट्रपति आपका कृतज्ञ हूँ।

भारत के लोग स्वाभाविक तौर पर और अत्यधिक सहजता के साथ आपके महान देश की जनता से जुड़े हैं।

और, व्यक्तिगत तौर पर भी मैंने हमेशा अपनी मित्रता को काफी महत्व दिया है।

इसलिए आज केवल यह कहना, उपयुक्त है कि हम अपनी मित्रता और सहयोग की शक्ति और उत्साह की दिशा में कुडनकुलम परमाणु बिजली संयंत्र की पहली इकाई को समर्पित करने के लिए एक साथ उपस्थित हैं। भारत-रूस मैत्री जिंदाबाद !

इस समर्पण कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित होने के लिए महामहिम पुतिन, मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ।

हमारे साथ उपस्थित होने के लिए जयललिता जी को भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

आप सबों को धन्यवाद।

आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।

शाहबाज हसीबी/सुधीर कुमार सिंह/मधुप्रभा

**पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
प्रधानमंत्री कार्यालय**

24-अक्टूबर-2016 20:57 IST

उर्जा गंगा परियोजना, प्रधानमंत्री पीएनजी पाइपलाइन और वाराणसी - इलाहाबाद रेल लाइन के दोहरीकरण की आधारशिला रखने के अवसर पर 24 अक्टूबर, 2016 को वाराणसी में प्रधानमंत्री का सम्बोधन

मैं सबसे पहले काशी वासियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब मैंने टीवी पर देखा, अखबारों में पढ़ा, कुछ यहां के स्थानीय नागरिकों ने मुझे फोन करके बताया कि हम काशी वालों ने छोटी दिवाली मना ली। 29 सितंबर को जब देश की सेना ने पराक्रम किया तो पूरा काशी झूम उठा। काशी वासियों ने देश के सुरक्षा बलों का जो गौरव गान किया, मां गंगा की आरती को जिस प्रकार से समर्पित किया, यहां का सांसद होने के नाते आपके द्वारा सेना का इतना सम्मान हो, गौरव हो तो मेरी खुशियों का कोई पार नहीं रहता।

ये आपने जो छोटी दिवाली मनाई थी उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कई वर्षों के बाद सवा सौ करोड़ देश वासी सेना के जवानों को अहसास करवाने में सफल हुए हैं कि आप अकेले नहीं हैं, सवा सौ करोड़ का देश आपके पीछे खड़ा है। अब हम बड़ी दिवाली मनाने जा रहे हैं। हम तो अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएंगे, अपनों के बीच खुशियां बांटेंगे, दीये जलाएंगे, अंधेरा हटाएंगे, रोशनी लाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये तब संभव होता है जब किसी मां का लाल सीमा पर तैनात होकर के हम लोगों के सुख चैन के लिए अपने आप को खपा देता है।

ये छोटी दिवाली मनाकर देश को आपने दिशा दी। मैं काशी वासियों का, उत्तर प्रदेश के नागरिकों का, हिंदुस्तान भर के नागरिकों का, काशी की धरती से आह्वान करता हूँ कि इस दिवाली में हम अपनों को जिस प्रकार से शुभकामनाएं देते हैं, उसी प्रकार से हम सेना के अपने जवानों को, हमारे सुरक्षा बलों को, दीपावली का संदेश भेजकर उनके प्रति अपने लगाव का अहसास करवाएंगे। चाहे वो थल सेना में हों, जल सेना में हों, वायु सेना में हों, कोस्ट गार्ड में हों, इंडो-तिब्बतन फोर्स में हों, असम राइफल्स में हों, बीएसएफ में हों, सीआरपीएफ में हों - हर कोई, सवा सौ करोड़ देश वासियों की सुरक्षा के लिए तैनात है। इस दीपावली में हम सब की तरफ से उनको एक संदेश जाना चाहिए।

भेजेंगे? कैसे भेजेंगे?

आप अपने मोबाइल से 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल करना। वहां आपको एक मैसेज आएगा। उस मैसेज से आप नरेंद्र मोदी एप अपने फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सेना के जवानों को संदेश भेजने के लिए एक जगह है, उससे आप संदेश भेजेंगे। देश के सुरक्षा बलों को आपके संदेश मिलेंगे।

देश के सुरक्षा बलों को हर पल लगना चाहिए कि हमारी जवानी हम देश के लिए लगा रहे हैं तो देश वासियों को हम पर कितना गौरव है, कितना अभिमान है। उन्हें ये प्रतिपल अनुभव होना चाहिए। सिर्फ बम, बंदूक और गोलियों की आवाज के दरमियान हों ये काफी नहीं है। दुनिया के कई देशों में, अगर सेना के जवान हवाई जहाज में जा रहे होते हैं, रेल से जा रहे हैं और वहां अन्य यात्री उन्हें देखते हैं तो सब तालियों से उनका गौरव गान करते हैं और वे वहां से गुजरते हैं। ये सामान्य स्वभाव बना हुआ है। हमारे देश में जब विशिष्ट परिस्थिति पैदा होती है, पराक्रम की बात आती है तब तो एकदम से देशभक्ति उमड़ पड़ती है, लेकिन फिर धीरे धीरे सब ठंडा हो जाता है। सेना के साथ, सुरक्षा बलों के साथ, एक आत्मीय, गौरवपूर्ण, सम्मानजनक नाता जोड़ने का कल्चर हमेशा बना रहना चाहिए। विशिष्ट अवसरों पर ही बना रहे ये काफी नहीं है।

इसलिए मैंने इस बार सेना के जवानों को संदेश भेजा है और देशवासियों को भी कहा है कि आप भी मेरे साथ इस संदेश में जुड़िए।

भाइयो-बहनो, आज मैं सबसे पहले इन सारे मंत्रियों का, उनके मंत्रालयों का आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र में आपने इतनी सारी योजनाएं लागू कीं और मेरे यहां के मतदाताओं की सुविधा के लिए आपने इतना बढ़िया-बढ़िया काम किया। मैं पहले आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं रेलवे विभाग के अधिकारियों का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपने मेरे स्वभाव को भली भांति समझ कर के प्रकल्प को समय से पहले पूरा कर दिया। वरना सरकारें ऐसी होती हैं कि

शिलान्यास एक सरकार करती है, उद्घाटन दूसरी या तीसरी सरकार के नसीब में आता है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदल जाती हैं लेकिन वो पत्थर वहीं पड़ा रहता है।

ये ऐसी सरकार है कि शिलान्यास भी हम ही करते हैं और उद्घाटन भी हम ही करना चाहते हैं। योजनाएं समय सीमा में होनी चाहिए। निर्धारित बजट में होनी चाहिए। हो सके तो समय भी बचना चाहिए, धन भी बचना चाहिए और काम उत्तम होना चाहिए। ये कल्चर विकसित करने का प्रयास दिल्ली में जो आपने सरकार बैठाई है वो कोशिश कर रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये हर क्षेत्र में होने वाला है।

आपने देखा होगा, हमारे जितने मंत्री यहां बोले, जितनी आपको कार्यक्रम की योजनाएं बताई उसके साथ-साथ समय भी बताया। क्योंकि मेरा एक आग्रह रहता है, मैं कार्यक्रम पर या किसी फाइल पर साइन करता हूं तो पूछता हूं जरा ये बताओ पूरा कब करोगे? योजनाएं सिर्फ अखबारों में छपने के लिए नहीं होती हैं, सिर्फ अखबारों में वाहवाही के लिए नहीं होती हैं, योजनाएं जनसामान्य के जीवन में बदलाव लाएं इसे कार्यान्वित करने के लिए होती हैं। और इस सरकार का आग्रह है कि हम जो योजनाएं लाएंगे, लागू करके रहेंगे।

अभी आपने यहां देखा, सुकन्या समृद्धि योजना। जिस दिन हमने यह योजना घोषित की होगी, अखबार में भी आई होगी, कुछ लोगों ने जाना, कुछ लोगों ने नहीं जाना और बात आई-गई हो गई लेकिन हम ऐसे नहीं करते, हम पीछे लगे रहते हैं कि बताओ भई कर रहे हो कि नहीं? सभी बच्चियों को लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? पीछे लग रहे हो कि नहीं लग रहे हो? तो देखो, कर रहे हैं।

यहां आपने देखा, मुझे कुछ परिवारों को गैस सिलेंडर देने का अवसर मिला। हमें मालूम है गैस सिलेंडर पाना पहले कितनी दिक्कत का काम हुआ करता था। सिफारिश लगानी पड़ती थी। सांसद के अगल-बगल घूमना पड़ता था। बड़े-बड़े अफसर भी एमपी को पकड़ते थे कि साहब मेरी ट्रांसफर यहां हुई है मैं यहां आया हूं जरा गैस का कनेक्शन मिल जाए मुझे, देखिए न बड़ी मुसीबत है। एमपी को 25 कूपन मिला करती थी गैस का कनेक्शन दिलवाने के लिए। और वो एमपी 25 कूपन लेकर घूमता रहता था, उसके पीछे 200-200 लोग घूमते रहते थे कि साहब एक कूपन मुझे भी दीजिए। ये सब चला गया। सरकार सामने से गरीबों को दूँद रही है, गरीबों के घर को दूँद रही है।

मेरा सपना है कि 3 साल में हिंदुस्तान के गरीब परिवारों के घर में जहां लकड़ी का चूल्हा जलता है, जहां खाना पकाने में हर मां के भीतर बहुत धुंआ जाता है, उन माताओं को धुंए से बचाना है। गरीब के घर में गैस का चूल्हा जलाना है। ये कोशिश कर रहा हूं।

लेकिन इसके साथ-साथ, आज वाराणसी में गैस पाइपलाइन के कार्यक्रम का शिलान्यास हो रहा है। रसोईघर में नल से पानी भी हर घर में आता होगा या नहीं उसका मुझे मालूम नहीं। अभी भी घर से बाहर पानी लेने के लिए लोगों को शायद जाना पड़ता होगा। मेरी कोशिश है और खासकर के काशी की माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद दीजिए कि रसोई घर में नल ऑन करने से गैस आ जाएगी, खाना पकना शुरू हो जाएगा। निर्धारित समय में सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च करके गैस की पाइपलाइन बिछाने की दिशा में आज कार्य आरंभ हो रहा है।

अर्थव्यवस्था में ऊर्जा का बड़ा महत्व होता है। गैस आधारित इकोनॉमी, फर्टिलाइजर के उत्पादन में गैस की जरूरत होती है। उसके लिए जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन का जो काम था वो तो होना ही है लेकिन उसके साथ हमने देश के सात शहरों, विशेष कर पूर्वी हिंदुस्तान में, पाइपलाइन से गैस देना तय किया है। ये शहर हैं वाराणसी, रांची, कटक, पटना, जमशेदपुर भुवनेश्वर, कोलकाता। उसके तहत आज मेरे संसदीय क्षेत्र के घरों में पाइपलाइन से गैस पहुंचाने की दिशा में काम हो रहा है।

यातायात में भी जहां आप पेट्रोल डीजल से गाड़ियां चलाते हैं, अब सीएनजी से गाड़ी चला पाएंगे। पेट्रोल-डीजल से सीएनजी सस्ता भी पड़ता है, पर्यावरण को भी फायदा करता है। यहां करीब 20 लाख वाहन हैं जिन्हें फायदा मिलेगा जब सीएनजी के स्टेशन लग जाएंगे। और इन सातों शहरों में बहुत बड़ी मात्रा में वाहन हैं, तो पर्यावरण को बहुत बड़ा लाभ होगा। देश को विदेशों से पेट्रोलियम लाना पड़ता है, उसमें भी आर्थिक रूप से देश की बचत होगी। तो एक ऐसी योजना जो जनसुविधा वाली भी है और भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए भी पर्यावरण की रक्षा करने वाली है।

ये मेरा साफ मत रहा है कि अगर हम सोचें भारत का कोई इलाका आगे बढ़ जाए तो देश आगे बढ़ जाएगा ये संभव नहीं है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब हिंदुस्तान के हर कोने में विकास हो, विशेषकर हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके में विकास हो। चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, पूर्वोत्तर के प्रदेश हों, असम हो - ये सारा क्षेत्र आर्थिक गतिविधि का केंद्र बनाना है तो हमें इस प्रकार की सुविधाओं से उसे जोड़ना होगा।

पिछले दिनों आपने देखा होगा काशी की संगीत की दुनिया को हैरिटेज में स्थान मिला। वो काशी के लिए गौरव का विषय था। ये सर्वविद्या का केंद्र है। संगीत के क्षेत्र में काशी ने देश और दुनिया को बहुत कुछ दिया है। उस विरासत को हैरिटेज के रूप में दुनिया के अंदर स्थान मिला। उसी से प्रेरणा लेकर के आज काशी का पोस्टल स्टैम्प .. और मैं चाहूंगा काशी के लोग तो अपनी डाक में काशी का ही ये पोस्टल स्टैम्प लगाने की आदत डालें। वो अपने आप में आपका परिचय बढ़ाता है। एक बार पोस्टल स्टैम्प जाता है तो दुनिया में टूरिज्म के लिए वो कारण होता है। उससे एक पहचान मिलती है। काशी का गौरव गान होता है। बहुत पहले शहरों की डाक टिकट की कल्पना हुई थी हमारे देश में, लेकिन वो मामला आगे बढ़ा नहीं। हमने काशी को इस काम के लिए चुना। फिर से एक बार शुरुआत हुई है और इसके कारण हमारे इस पुरातन शहर की एक पहचान नए तरीके से दुनिया के सामने पहुंचाने में ये एक काम होगा।

आज यहां किसानों के लिए भी एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण राजा तालाब प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। हमारे किसान बड़े शहरों के अगल बगल में सब्जी पैदा करते हैं। ये राजा तालाब एक ऐसी जगह है जो पूरब, पश्चिम और उत्तर में रोड़ और रेल की कनेक्टिविटी में केंद्र बिंदु है। यही वो इलाका है जहां हमारे किसान सबसे ज्यादा सब्जी, फलों और फूलों की खेती करते हैं। अगर उनको इस प्रकार की सुविधा मिले और उनके लिए बर्बादी बच जाए और परिवहन की सुविधा हो जाए तो हमारे किसान को सबसे ज्यादा फायदा होगा। और ये व्यवस्था ऐसी है कि इस इलाके के किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। वो अपनी मर्जी से जब दाम मिलेगा तो माल बेच सकता है नहीं तो तब तक अपना माल सुरक्षित रख सकता है। सुविधा मिल जाए, व्यवस्था मिल जाए, परिवहन की व्यवस्था से वो जुड़ जाए तो किसान न सिर्फ इस इलाके में बल्कि वो कोलकाता से लेकर दिल्ली तक कहीं पर भी अपनी सब्जियां बेचने के लिए पहुंचा सकता है। यहां की फूलगोभी वगैरह तो बड़ी प्रसिद्ध है। यहां की चीजें बड़ी स्वादिष्ट हैं। मां गंगा का आशीर्वाद है यहां के कृषि उत्पादन पर। उसका एक अनोखा टेस्ट भी है। तो इसके कारण बाजार में उसकी एक पहचान बनेगी।

आज हमारे मनोज सिन्हा जी ने काशी को एक और गौरव दिया। डाक विभाग हमारे यहां की बहुत पुरातन व्यवस्था है। जब तक तकनीकी नहीं आई थी डाकिया हर घर में इंतजार का कारण हुआ करता था। डाक आए या न आए लेकिन हर परिवार राह देखता था कि डाकिया आकर तो नहीं चला गया? अगर बेटा बाहर रहता है तो वो हर दिन डाकिए को याद करते थे। डाक का अपना एक महत्व है।

नए समय में डाक का स्वरूप अब बदल चुका है। हम डाक को बैंकिंग क्षेत्र में तब्दील कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। देश में आज जितनी बैंकों की शाखाएं हैं उतनी ही अकेली डाकघरों की शाखाएं हैं। डेढ़ लाख से ज्यादा। वे सब बैंकिंग का काम करेंगी। वो जब एक नया जोन बनता है तो यहां कि सुविधाओं पर एक विशेष निगरानी बनती है, कुशलता आती है और परिणाम मिलता है। वो काम करने के लिए एक क्षेत्रीय व्यवस्था काशी के आस पास के जिलों को जोड़कर के बनी है। नए जोन का निर्माण किया गया है।

आजकल ई-कॉमर्स का मामला बहुत बढ़ रहा है। लोग ऑनलाइन अपनी चीजें खरीदते हैं। लेकिन वो वक्त दूर नहीं होगा जब पोस्ट ऑफिस डिलीवरी के बहुत बड़े केंद्र बनेंगे। आज मनरेगा के पैसे देने हों, स्कॉलरशिप के पैसे देने हों, पेंशन के पैसे देने हों - बैंकों की शाखा कम हैं। ये सुविधा बढ़ने के कारण जो बुजुर्ग लोग हैं, विद्यार्थी हैं, विधवाएं हैं उनको डाक और बैंक जुड़ने के कारण ये सुविधाएं सरलता से उपलब्ध होंगी। ये होने के कारण व्यापारी वर्ग को भी खासकर छोटे-छोटे व्यापारियों को अपना कारोबार चलाने के लिए एक नई सुविधा उपलब्ध होगी। इस काम को भी आज आपके सामने प्रस्तुत किया है।

रेल हमारे देश की बहुत पुरानी व्यवस्था है। जब संसद में बजट आता और रेल मंत्री हजारों लाखों करोड़ की घोषणाएं कर दें, कोई सांसद उनकी सुनता नहीं था, लेकिन जैसे ही वे बोलना शुरू होते थे कि फलाने शहर से फलाने शहर तक एक डिब्बा जोड़ दिया जाएगा तो तुरंत सांसद तालियां बजानी शुरू करते थे। फलानी जगह पर स्टॉपेज दिया जाएगा, तालियां बजती थीं। फलानी जगह पर नई ट्रेन लगाई जाएगी तो तालियां बजती थीं। रेलवे बजट इसी पर सीमित हो गया कि किस सांसद के कौन से इलाके में ट्रेन रुकेगी या नहीं रुकेगी, जाएगी या नहीं जाएगी। यहां पर रेल सीमित हो गई।

रेल भारत का इतना बड़ा नेटवर्क है लेकिन उसके हाल चाल रूप रंग ढंग पिछली शताब्दी के हैं। हमने सपना देखा है कि रेल को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। रेल की गति बढ़ाने की आवश्यकता है। रेल के इलेक्ट्रिकल कनवर्जन की आवश्यकता है। गेज कनवर्जन की आवश्यकता है। दूर-सुदूर इलाकों से जोड़ने की आवश्यकता है और इसलिए एक बहुत बड़ा प्लान जैसा हमारे रेल मंत्री जी कह रहे थे, आजादी के बाद जितने रुपये खर्च किए गए, जितना काम नहीं हुआ पिछले ढाई साल में और पिछले महीनों में हमने इतना काम किया है। और इसी के तहत ये जब इलाहाबाद डबल लाइन हो जाएगी, नया पुल बन जाएगा, गति भी बढ़ेगी, व्यापार को भी फायदा होगा। एक बार इस प्रकार का गतिशील आधारभूत ढांचा उपलब्ध हो जाता है तो आर्थिक गतिविधि भी तेज हो जाती है। ये सिर्फ पटरियों का खेल नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेन दौड़ने

वाला खेल नहीं है, ये पूरी अर्थव्यवस्था को बदल देता है। इस काम के लिए ये बड़ा अहम कदम आज हमने यहां उठाया है। उसका भी लाभ आपको मिलने वाला है।

आज बिजली के लिए भी एक लोकार्पण हुआ। बिजली होती तो है लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि बिजली के कारखाने में बिजली बनने से बिजली मिलती नहीं है। बिजली का कारखाना भी लग गया, तार भी लग गए तो उससे बिजली नहीं आ जाती। जैसे पानी के बहाव को पहुंचाने के लिए बांध की जरूरत पड़ती है या ट्यूबवेल से जरिए पानी को ऊपर ले जाकर टंकी में भरने के बाद पानी नीचे पहुंचता है, वैसे बिजली को भी इस प्रकार के सब-स्टेशन की जरूरत पड़ती है जिससे बिजली को आगे पहुंचाने के लिए धक्का लगता है।

ये बड़ा खर्चीला काम होता है लेकिन सब-स्टेशन न हो तो बिजली आती है, जाती है, कभी टीवी जल जाते हैं, कभी मोटर जल जाती है, कभी एसी जल जाता है, स्थिरता नहीं आती। क्वालिटी पावर नहीं मिलता है। इसके लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। लेकिन ज्यादातर सरकारों को इस प्रकार के खर्च करने से डर लगता है। उनको लगता है ठीक है लोग चला लेंगे, बिजली आई न आई वो थोड़े दिन चलाते रहेंगे। नहीं, क्वालिटी बिजली होती है तो आर्थिक विकास का एक बहुत बड़ा सरल रास्ता हो जाता है। उद्योगपति भी पैसे तब लगाते हैं जब क्वालिटी बिजली मिलती है। आती है, जाती है, पूछते हैं, करते हैं, हुआ, नहीं हुआ इन बातों से कभी विकास नहीं होता है। ये जो पावर के सब-स्टेशन डाले गए हैं जिसका उद्घाटन हुआ है वो क्वालिटी पावर की गारंटी देते हैं।

एक प्रकार से आज किसी एक समारोह में करीब-करीब 5000 करोड़ रुपये का काम काशी की धरती को अर्पित हो रहा है।

ये छोटा काम नहीं है। और बड़ी-बड़ी योजनाएं मैं कहूं तो आज सात योजनाएं मेरे काशी वासियों के सामने लोकार्पण के रूप में या शिलान्यास के रूप में मैंने रखी हैं। एक तरह से ये सप्तर्षि है। जैसे आकाश में सप्तर्षि दिशा का काम करते हैं, सप्तर्षि को देखकर के समंदर में नाविक अपनी दिशा तय करता है, पहले के जमाने में जंगलों से गुजरने वाले लोग सप्तर्षि को देख अपना रास्ता तय करते थे। काशी की विकास की राह तैयार करने वाला ये सप्तर्षि आज मुझे यहां की धरती को देने का अवसर मिला है।

काशी का अविरल प्यार मुझे मिलता रहा है। भरपूर प्यार मिलता रहा है। मैं आपका हृदय से बहुत-बहुत आभारी हूं और मुझे विश्वास है कि विकास की यात्रा तेज गति से पूरे पूर्वी भारत को बदलाने का काम करेगी और काशी अपनी ताकत दिखा कर रहेगी इस विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
प्रधानमंत्री कार्यालय

05-दिसंबर-2016 11:45 IST

पेट्रोटेक उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री के संबोधन का मूलपाठ
विषय: हाइड्रोकार्बन भविष्य के ईंधन के लिए - विकल्प और चुनौतियां

मेरे सहयोगी धर्मप्रधान जी, विदेशों से आए तेल एवं गैस मंत्रियों, कार्यकारी अधिकारियों और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के विशेषज्ञों, गणमान्य जनों एवं विशेष अतिथितियों,

ऊर्जा आर्थिक विकास की एक प्रमुख कुंजी है। सतत, स्थिर और उचित कीमत वाली ऊर्जा आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है ताकि वह एक नई ऊंचाई को छू सके। आने वाले कई वर्षों के लिए हाइड्रोकार्बन ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बना रहेगा। इसलिए इस सम्मेलन का विषय "हाइड्रोकार्बन भविष्य के ईंधन के लिए: विकल्प और चुनौतियाँ" उपयुक्त है और समय पर है।

आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह वृद्धि नीतिगत उपायों की एक श्रृंखला के द्वारा समर्थित है। हमारी नीतियाँ छोटी अवधि सुखियों के बजाय भारत की दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक संभावनाओं में सुधार पर केंद्रित हैं। हमारे प्रयास आर्थिक वृद्धि और विकास के मामले में परिणाम दिखा रहे हैं।

तेजी से विकास इसके अलावा, दूसरों की तुलना में हमारी अर्थव्यवस्था सबसे अधिक स्थिर है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में जब अनिश्चितता का दौर जारी है उसी समय भारत जबरदस्त लचीलापन दिखाया है। हमारे चालू खाते के घाटे में तेजी से सुधार हुआ है और जून की तिमाही में एक दशक से भी कम स्तर पर पहुंच गया। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2015-16 में उच्चतम स्तर पर था जबकि दुनिया में एफडीआई की दर गिरी है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अनुसार प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत बैंकिंग संकट की चपेट में कम है।

भारत की अर्थव्यवस्था के 2040 तक पांच गुना की दर से विकास करने की उम्मीद है। एक अनुमान के मुताबिक भारत 2013 और 2040 के बीच एक चौथाई विकासशील वैश्विक ऊर्जा की मांग की ओर अग्रसर है। पूरे यूरोप की तुलना में भारत में 2040 तक अधिक तेल की खपत होने की उम्मीद है। हम उम्मीद करते हैं कि 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदार 25 फीसदी दो जाएगी जबकि अभी यह दर 16 फीसदी पर रुकी हुई है।

परिवहन बुनियादी ढांचे में भी कई गुना वृद्धि की संभावना है। तेरह मिलियन की वाणिज्यिक वाहन आबादी 2040 तक 56 मिलियन तक पहुंच जाने का अनुमान है। नागरिक उड्डयन में, भारत इस समय दुनिया में आठवां सबसे बड़ा बाजार है और 2034 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन बनने के लिए तैयार है। विमानन क्षेत्र में विकास के चलते 2040 तक विमानन ईंधन की मांग चार गुना बढ़ने की उम्मीद की जाती है। यह सब ऊर्जा की मांग को प्रभावित करेगा।

साथियों,

हाइड्रोकार्बन भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। तेजी से विकास की संभावना भारत के ऊर्जा क्षेत्र पर एक बड़ी जिम्मेदारी देती है। मुझे खुशी है कि भारत और विदेशों से इतने सारे प्रतिभागियों ने यहाँ आने के लिए समय निकाला है। मुझे यकीन है कि हम सभी के अनुभव और एक दूसरे की विशेषज्ञता से लाभ होगा। मैं इस अवसर पर हाइड्रोकार्बन क्षेत्र से जुड़ी उम्मीदों को लेकर अपने विचार आप के साथ साझा करना चाहता हूँ और हमारा प्रयास ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने को लेकर है।

ऊर्जा को लेकर सामान्य रूप से और विशेष रूप से हाइड्रोकार्बन भारत के भविष्य के लिए मेरी दृष्टि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत को ऐसी ऊर्जा की जरूरत है जो गरीबों के लिए सुलभ हो। ऊर्जा के इस्तेमाल में दक्षता की जरूरत है। एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक होने के नाते, भारत जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने, उत्सर्जन को रोकने और एक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए भारत को ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत है। इसलिए, भारत की ऊर्जा भविष्य के लिए मेरी दृष्टि चार स्तंभों है।

--ऊर्जा की पहुंच
--ऊर्जा दक्षता
--ऊर्जा स्थिरता
--ऊर्जा सुरक्षा

मैं ऊर्जा के उपयोग के साथ शुरुआत करता हूँ। भारत के कुछ अमीर लोग जब हाइब्रिड कार खरीद रहे होते हैं उसी समय एक गरीब खाना बनाने के लिए लकड़ी का जलावन खरीद रहा होता है। भोजन पकाने के लिए लकड़ी या अन्य बायोमास का इस्तेमाल ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे उनकी उत्पादकता घटती है। हमने 50 मिलियन परिवारों को रसोई गैस मुहैया करने के साथ उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है। एक ही झटके में, इस कार्यक्रम के चलते

स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है, उत्पादकता बढ़ जाती है और हानिकारक उत्सर्जन कम हो जाता है। रसाई गैस का कनेक्शन लेने के लिए पहली बार सरकार खुद खर्च उठाएगी लेकिन उसके बाद ग्राहक को पूरा भुगतान करना होगा। इस कार्यक्रम के तहत महज सात महीनों में ही करीब 10 मिलियन परिवारों को गैस कनेक्शन मुहैया कराया गया है। सरकार ने अगले पांच वर्षों में एक करोड़ घरों तक पाइपड प्राकृतिक गैस का विस्तार करने का लक्ष्य तय किया है। हम तीस हजार किलोमीटर तक पाइप गैस लाइन के राष्ट्रीय गैस ग्रिड नेटवर्क के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी यह पंद्रह हजार किलोमीटर तक फैला हुआ है। हम कम विकसित पूर्वी क्षेत्र के लिए एक नई गैस पाइपलाइन का निर्माण कर रहे हैं जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेंगे। हम मार्च 2018 तक भारत में हर गांव तक बिजली की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं।

अब ऊर्जा दक्षता पर बात करने की बारी है। भारत की स्थिति वाणिज्यिक परिवहन क्षेत्र में विषम है। माल ढुलाई का अनुपात सड़क मार्ग से बढ़ रहा है। ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने रेलवे को प्राथमिकता दे रही है। हमने 2014-15 और 2016-17 के बीच अधिक से अधिक एक सौ प्रतिशत तक की रेलवे में सार्वजनिक पूंजी निवेश में वृद्धि की है। हम समर्पित फ्रेट कॉरिडोर पूरा कर रहे हैं। हम मुंबई और अहमदाबाद के बीच एक उच्च गति रेल गलियारे का निर्माण कर रहे हैं जो हवाई यात्रा से ज्यादा ऊर्जा दक्षता वाला होगा। हम अंतर्देशीय और तटीय दोनों क्षेत्रों में जलमार्ग के लिए एक बड़ा जोर दिया है। हमारी सागरमाला परियोजना भारत के लंबे समुद्र तट को जोड़ेगी। हमने बड़ी नदियों पर भी नए अंतर्देशीय शिपिंग मार्गों को खोल दिया है। इन कदमों से ऊर्जा दक्षता में सुधार होगा। बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर कानून को पारित कर दिया गया है। राज्य की सीमाओं पर भौतिक बाधाओं को दूर करके जीएसटी लंबी दूरी के परिवहन को और आगे बढ़ाने में दक्षता को गति देगा।

विकासशील देशों के तेल मंत्री ऊर्जा मूल्य निर्धारण की संवेदनशीलता को जानते हैं। इसके अलावा, हमने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को अनियंत्रित कर दिया है। रसाई गैस की कीमतों को भी बाजार तय करेगा। कमजोर और मध्यम वर्ग की रक्षा के लिए 169 मिलियन बैंक खातों में सीधे सब्सिडी का भुगतान किया जा रहा है। इससे रसाई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी की तमाम खामियों और उसके दुरुपयोग को खत्म किया जा सकेगा। इससे बड़ी बचत हो रही है। इन उपायों से भी ऊर्जा के उपयोग की दक्षता में वृद्धि हुई है।

मेरे लिए ऊर्जा स्थिरता, एक पवित्र कर्तव्य है। यह कुछ ऐसा है जो भारत को प्रतिबद्धता से बाहर करता है, अनिवार्यता से नहीं। भारत अगले पंद्रह वर्षों में अपने 2005 के स्तर से अपने सकल घरेलू उत्पाद का कार्बन तीव्रता में तैंतीस प्रतिशत की कमी करने के लिए खुद करने में पहल की है। हमने प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत प्रारंभिक बिंदु के बावजूद कम किया है। हम 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा चालीस प्रतिशत का उत्पादन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैंने 2022 तक अक्षय ऊर्जा उत्पादन का 175 गीगावाट का एक विशाल लक्ष्य निर्धारित किया है। इन प्रयासों के लिए धन्यवाद, क्षमता में वृद्धि हुई है और अक्षय ऊर्जा की कीमतें घटी हैं। हमने एलईडी प्रकाश व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा जोर दिया है।

सीएनजी, एलपीजी, जैव ईंधन और परिवहन क्षेत्र के लिए स्वच्छ ईंधन हैं। हम और विकल्पों की तलाश के लिए बंजर भूमि पर बायोडीजल का उत्पादन करने की जरूरत है। इससे किसानों को आर्थिक मदद मुहैया कराने में मदद मिलेगी। दूसरी और तीसरी पीढ़ी के लिए देश को मिल रही ऊर्जा चुनौतियों का सामना करने के लिए जैव ईंधन और ईंधन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास किए जाने की जरूरत है।

अब मैं ऊर्जा सुरक्षा पर बात कर रहा हूँ। हमें अपने घरेलू तेल और गैस के उत्पादन में वृद्धि और आयात पर निर्भरता कम करने की जरूरत है। मैंने 2022 तक दस प्रतिशत तक आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे बढ़ती तेल की खपत की अवधि के दौरान हासिल करना होगा।

घरेलू हाइड्रोकार्बन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत और अनुकूल निवेश नीतिगत ढांचा हमारे पास है। लगभग दो दशक पहले, भारत ने नई अन्वेषण लाइसेंसिंग व्यवस्था शुरू की थी। भारत के इस कदम ने एक सौ प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी और निजी कंपनियों के लिए इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए एक अवसर प्रदान किया जिससे निवेश आए और वे भारतीय अपस्ट्रीम क्षेत्र में संचालित हो सकें। हालांकि, कई कारकों ने भारत के घरेलू तेल और गैस के उत्पादन को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित किया है।

भारत को एक सच्चे निवेशक अनुकूल गंतव्य बनाने के लिए हम एक नए हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और उत्पादन नीति के साथ आए हैं। यह अन्वेषण और हाइड्रोकार्बन के सभी रूपों के लिए उत्पादन को लेकर लाइसेंस ढांचा प्रदान करता है जिसमें शेल तेल, गैस और कोल बेड मीथेन शामिल है।

- खुला रकबा नीति बोलीदाताओं के लिए है, जो इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें अमुमति है।
- राजस्व साझा मॉडल लाभ बांटने के बजाय विवादों की गुंजाइश को कम करने के लिए
- कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता होगी

पिछले साल, हमने नए सीमांत क्षेत्रों नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत, सड़सठ क्षेत्रों में बोली लगाने के लिए की पेशकश की गई। सड़सठ के अलावा, अनुमान है कि इन क्षेत्रों में 89 मिलियन मीट्रिक टन तेल के साथ साथ तेल के बराबर गैस के भंडार धारण करने के लिए कर रहे हैं। अनुमान के अनुसार वसूली भंडार तीस मिलियन मीट्रिक टन के आदेश हैं। मैं समझता हूँ कि यह एक उत्साहजनक प्रतिक्रिया है जो कई वैश्विक कंपनियों के भाग लेने के साथ बोली लगाने की प्रक्रिया को प्राप्त किया गया है। डाउनस्ट्रीम क्षेत्र अब और अधिक खुला है, जिससे सभी मार्केट दिग्गजों के काम करने में आसानी होगी। इसके परिणामस्वरूप प्रतियोगिता दक्षता और हमारे विपणन कंपनियों के प्रभाव में वृद्धि होगी।

हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों को सक्रिय विदेश नीति और कूटनीति ऊर्जा को मजबूत करने में हमें मदद कर रहा है। मुझे आशा है कि हमारे तेल और गैस क्षेत्र की कंपनियों को अपने विदेशी समकक्षों के साथ करार करने में और अधिक इक्विटी तेल के लिए पता लगाने का अवसर मुहैया कराएगा। 5.6 बिलियन डॉलर के निवेश से रूस में हाइड्रोकार्बन परिसंपत्तियों के हाल के अधिग्रहण से इक्विटी तेल के बराबर के 15 मिलियन टन के लिए है। यह एक उदाहरण भर है। भारतीय ऊर्जा कंपनियों बहुराष्ट्रीय हो जाना चाहिए और भारत-मध्य पूर्व, भारत-मध्य एशिया और भारत-दक्षिण एशिया ऊर्जा गलियारों की दिशा में काम करना चाहिए।

प्राकृतिक गैस अगली पीढ़ी जीवाश्म ईंधन है, जो किफायती और कम प्रदूषक है। हमने गैस अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने को प्राथमिकता दी है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जबकि बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात भी किया जाना चाहिए। भारत में अक्षय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ने की प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में संतुलन लाने में अहम भूमिका होगी। संतुलन और बढ़त शक्ति प्रदान करेगी क्योंकि गैस आधारित ऊर्जा मुश्किल स्थिति में है।

दोस्तों, इस दृष्टि को हासिल करने के लिए हमें इस परियोजना को लेकर और संसाधन प्रबंधन के मामले में बहुत कुशल होने की जरूरत है। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत को सुधार करने की जरूरत है। यह न केवल हमारे रिफाइनिंग और प्रसंस्करण क्षमता में सुधार होगा, बल्कि समय और कुशल परियोजना को पूरा किया जा सकेगा।

भारत हमेशा से बौद्धिक क्षमता और उद्यम के मामले में दूसरों के लिए एक प्रेरणा कारक रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि "मेक इन इंडिया", "स्टार्टअप इंडिया", और "स्टैंडअप इंडिया" जैसी पहलों से भारत के तेल एवं गैस क्षेत्र में युवाओं को उपक्रम शुरू करने के अवसर और नवोन्मेषी आइडिया मिलेंगे। रिफाइनिंग, नैनो, उत्प्रेरक विकास में प्रौद्योगिकी विकास एवं जैव ईंधन और वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रों में हमें ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। इंडियन ऑयल का सफलतापूर्वक इंडमैक्स प्रौद्योगिकी विकास इसका एक उदाहरण है।

वैश्विक हाइड्रोकार्बन कंपनियों के लिए मेरा संदेश है: हम आपको मेक इंडिया कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करते हैं। कारोबार को सुगम बनाने को लेकर हमारे प्रयासों के चलते भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता है कि लाल फीताशाही की जगह रेड कॉरपेट को लेकर हमारी प्रतिबद्धता मजबूत है।

दोस्तों,

एक तरफ, बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हमें सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा के स्रोतों की जरूरत है। हाइड्रोकार्बन इस मिश्रण का एक अनिवार्य हिस्सा हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर हमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। मुझे यकीन है, इस शानदार सभा में नवीन विचार आएंगे जहां हाइड्रोकार्बन एक अधिक कुशल और भविष्य के स्थायी ईंधन के लिए नया रास्ता प्रदान करेगा।

मैं सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन देता हूँ। मैं भारत में ऊर्जा क्षेत्र के परिवर्तन का एक हिस्सा बनने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।

AKT/AK/VS

